मिशन मौसम

11 सितंबर 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 'मिशन मौसम' को मंजूरी दी।

प्रमुख बिंदु

- यह पूर्वानुमान, मॉडलिंग और प्रसार में भारत के मौसम विभाग की क्षमताओं को उन्नत करने का एक मिशन है।
- **बजट**: इसके कार्यान्वयन के पहले दो वर्षों के लिए इसका **बजट 2,000 करोड़ रुपये** होगा।
- **लक्ष्य:** मिशन का लक्ष्य मौसम निगरानी, मॉडलिंग, पूर्वानुमान में सुधार के लिए भारी निवेश करना है, जिससे कृषि, आपदा प्रबंधन, रक्षा, पर्यावरण, विमानन, जल संसाधन, बिजली, पर्यटन, शिपिंग, परिवहन, ऊर्जा और स्वास्थ्य जैसे कई प्रमुख क्षेत्रों को सीधे लाभ मिलेगा।
  - इसका लक्ष्य देश में मौसम और पूर्वानुमान सेवाओं के सभी पहलुओं को कवर करना है।
- **उद्देश्य**: मिशन का प्राथमिक उद्देश्य विभिन्न भौगोलिक और लौकिक पैमानों पर सटीक और समय पर **मौसम पूर्वानुमान और चेतावनियां प्रदान करना,** चरम मौसम की घटनाओं से पहले चेतावनियां और अलर्ट प्रदान करना, मौसम हस्तक्षेप शुरू करना है जो कोहरे, ओलावृष्टि और वर्षा के प्रबंधन में मदद करेगा, इसके अलावा कर्मियों की क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण भी शामिल है।
- **कार्यान्वयन**: मिशन मौसम का नेतृत्व पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा वित्तपोषित तीन संस्थानों - **आईएमडी, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान, पुणे, तथा राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र, नोएडा** द्वारा किया जाएगा।
  - इन संस्थानों को अन्य पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय संस्थानों (भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र, राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं महासागर अनुसंधान केंद्र, तथा राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान) के साथ-साथ सहयोगी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों, शिक्षाविदों और उद्योगों द्वारा समर्थन दिया जाएगा, जिससे मौसम एवं जलवायु विज्ञान तथा सेवाओं में भारत की अग्रणी स्थिति को और बढ़ावा मिलेगा।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-IV

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई-IV) के चौथे चरण के कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी।

प्रमुख बिंदु

- **कार्यान्वयन वर्ष:** इसे वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2028-29 तक के लिए अनुमोदित किया गया है।
- **बजट परिव्यय:** इसे कुल 70,125 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ मंजूरी दी गई है। इसमें केंद्र का हिस्सा 49,087.50 करोड़ रुपये और राज्य का हिस्सा 21,037.50 करोड़ रुपये है।
- इस योजना के तहत, जनगणना 2011 के अनुसार, मैदानी क्षेत्रों में **500+ आबादी वाली, पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 250+, विशेष श्रेणी के क्षेत्रों** (जनजाति अनुसूची V, आकांक्षी जिले/ब्लॉक, रेगिस्तानी क्षेत्र) और एलडब्ल्यूई प्रभावित जिलों में 100+ आबादी वाली 25,000 असंबद्ध बस्तियों को कवर किया जाएगा।

PMGSY

Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana

(Prime Minister's Rural Roads Programme)

- इस योजना के तहत असम्बद्ध बस्तियों को 62,500 किलोमीटर बारहमासी सड़कें उपलब्ध कराई जाएंगी। बारहमासी सड़कों के संरेखण के साथ आवश्यक पुलों का निर्माण भी किया जाएगा।

लाभ

- सभी मौसमों के लिए उपयुक्त सड़कें दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों के अपेक्षित सामाजिक-आर्थिक विकास और परिवर्तन के लिए उत्प्रेरक की भूमिका निभाएंगी।
- बस्तियों को जोड़ते समय, निकटवर्ती सरकारी शैक्षणिक, स्वास्थ्य, बाजार, विकास केंद्रों को, जहां तक संभव हो, स्थानीय लोगों के लाभ के लिए बारहमासी सड़क से जोड़ा जाएगा।

पीएम ई-ड्राइव योजना

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई) के 'पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव क्रांति इन इनोवेटिव व्हीकल एन्हांसमेंट (पीएम ई-ड्राइव) योजना' नामक योजना के कार्यान्वयन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

प्रमुख बिंदु

- इस नई पहल का उद्देश्य पूरे भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को अपनाने में तेजी लाना है, जो कि **प्रमुख (हाइब्रिड एवं) इलेक्ट्रिक वाहनों के तेजी से अपनाने और विनिर्माण (फेम) कार्यक्रम का स्थान लेगा।**
- **बजट परिव्यय:** इस योजना को 10,900 करोड़ रुपये के बजट के साथ दो वर्षों के लिए मंजूरी दी गई है।

- **योजना के प्रमुख घटक हैं:**
  - इस योजना के तहत 24.79 लाख इलेक्ट्रिक दोपहिया, 3.16 लाख ई-तीन पहिया और 14,028 ई-बसों को सहायता दी जाएगी।
  - इलेक्ट्रिक दोपहिया, इलेक्ट्रिक तिपहिया, ई-एम्बुलेंस, ई-ट्रक और अन्य उभरते इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लिए 3,679 करोड़ रुपये की सब्सिडी/मांग प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
  - राज्य परिवहन उपक्रमों और सार्वजनिक परिवहन एजेंसियों द्वारा 14,028 ई-बसों की खरीद के लिए 4,391 करोड़ रुपये की राशि भी प्रदान की गई है।
  - ई-एम्बुलेंसों की तैनाती के लिए 500 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं।

आगे का मार्ग

- पीएम ई-ड्राइव योजना से ईवी उद्योग को महत्वपूर्ण प्रोत्साहन और समर्थन मिलने, विकास को बढ़ावा मिलने और देश के कार्बन उत्सर्जन में कमी आने की उम्मीद है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रमुख योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB PM-JAY) के तहत आय की परवाह किए बिना 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य कवरेज को मंजूरी दी है।

प्रमुख बिंदु

- वरिष्ठ नागरिकों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी।
- इससे देश के करीब 4.5 करोड़ परिवार लाभान्वित होंगे, जिनमें करीब 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिक शामिल होंगे।
- **विशिष्ट कार्ड:** पात्र वरिष्ठ नागरिकों को एबी पीएम-जेएवाई के अंतर्गत एक नया विशिष्ट कार्ड जारी किया जाएगा।
- **कवरेज:** एबी पीएम-जेएवाई के तहत पहले से ही कवर किए गए परिवारों से संबंधित 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को अपने लिए प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक का अतिरिक्त टॉप-अप कवर मिलेगा।
  - 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के अन्य सभी वरिष्ठ नागरिकों को परिवार के आधार पर प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक का कवर मिलेगा।

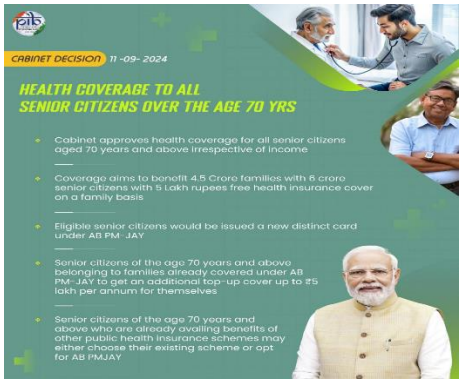

- 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक जो पहले से ही केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना, पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना, आयुष्मान केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल जैसी अन्य सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं, वे या तो अपनी मौजूदा योजना चुन सकते हैं या एबी पीएमजेएवाई का विकल्प चुन सकते हैं।
- 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक जो निजी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों या कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत है, वे एबी पीएम-जेएवाई के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के पात्र होंगे।

- एबी पीएम-जेएवाई दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित स्वास्थ्य आश्वासन योजना है, जो **12.34 करोड़ परिवारों के 55 करोड़ व्यक्तियों को द्वितीयक और तृतीयक देखभाल अस्पताल में भर्ती के लिए प्रति वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य कवर प्रदान करती है।**
- इस योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों के सभी सदस्यों को शामिल किया गया है, चाहे उनकी आयु कुछ भी हो। इस योजना के अंतर्गत 7.37 करोड़ अस्पताल में भर्ती मरीजों को शामिल किया गया है, जिनमें 49 प्रतिशत लाभार्थी महिलाएं हैं। इस योजना के अंतर्गत आम जनता को 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक का लाभ हुआ है।
- 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए कवर का विस्तार करने की घोषणा पहले माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा अप्रैल 2024 में की गई थी।

IDAX-24

12 सितंबर 2024 को रक्षा मंत्री ने भारत रक्षा विमानन प्रदर्शनी IDAX-24 का उद्घाटन किया।

प्रमुख बिंदु

- **लक्ष्य**: आईडीएएक्स का उद्देश्य तरंग शक्ति 2024 में भाग लेने वाली वैश्विक वायु सेनाओं के निर्णयकर्ताओं और अंतिम उपयोगकर्ताओं के व्यापक स्पेक्ट्रम के समक्ष भारतीय विमानन उद्योगों के स्वदेशी कौशल और अदम्य भावना का प्रदर्शन करना है।
- **मेजबान:** इसका आयोजन जोधपुर में भारतीय वायु सेना द्वारा किया जाता है।
- यह 12-14 सितंबर 2024 को आयोजित होने वाला है।
- इसमें उद्योग जगत की शानदार भागीदारी होगी और उत्पादों, प्रौद्योगिकियों की एक विस्तृत श्रृंखला पेश की जाएगी।
- यह भारतीय दर्शकों के लिए डीपीएसयू, डीआरडीओ, निजी उद्योगों (टियर-I, II, III) और शीर्ष स्टार्ट-अप सहित भारतीय विमानन उद्योग के प्रतिभागियों को देखने, अनुभव करने और उनके साथ बातचीत करने का एक अवसर होगा।
- iAF नवप्रवर्तकों, स्टार्टअप्स और एमएसएमई को प्रोत्साहित करने, नवीन समाधानों की पहचान करने, उन्हें विकसित करने और उन्हें लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

सैन्य अभ्यास

ईस्टर्न ब्रिज VII

रॉयल ओमान वायु सेना और भारतीय वायु सेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास

- अभ्यास ईस्टर्न ब्रिज VII का सातवां संस्करण 11 से 22 सितंबर 2024 तक ओमान के मसीराह वायु सेना बेस पर आयोजित किया जाएगा।
- इस अभ्यास में भारतीय वायुसेना की एक टुकड़ी भाग ले रही है जिसमें मिग-29, जगुआर और सी-17 शामिल हैं।
- अभ्यास ईस्टर्न ब्रिज VII का उद्देश्य सामरिक और परिचालन कौशल में सुधार करना, आपसी समझ को बढ़ावा देना और विविध परिदृश्यों में प्रभावी ढंग से सहयोग करने के लिए दोनों वायु सेनाओं की क्षमता को बढ़ाना है।

महत्वपूर्ण दिन/तारीख

12 सितंबर

अंतर्राष्ट्रीय दक्षिण-दक्षिण सहयोग दिवस

- 12 सितम्बर को संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दक्षिण-दक्षिण सहयोग दिवस मनाया जा रहा है।
- विषय: इस वर्ष का विषय है "दक्षिण-दक्षिण सहयोग के माध्यम से बेहतर कल"।
- 12 सितंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला यह दिवस सदस्य देशों को दक्षिण-दक्षिण सहयोग के मूल्य और लाभों की पुष्टि करने का अवसर प्रदान करता है।
- दक्षिण-दक्षिण सहयोग दक्षिण के लोगों और देशों के बीच एकजुटता की अभिव्यक्ति है जो उनके राष्ट्रीय कल्याण, उनकी राष्ट्रीय और सामूहिक आत्मनिर्भरता और सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा सहित अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सहमत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में योगदान देता है।

अन्य राज्यों से महत्वपूर्ण समसामयिकी

महाराष्ट्र

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने मुंबई में **वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर अकुरली पुल का उद्घाटन** किया।

नागालैंड

नागालैंड में राज्य सरकार ने **चुमुकेदिमा, निउलैंड और दीमापुर जिलों में इनर लाइन परमिट (आईएलपी)** के कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी है।

विविध

- स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में **विश्व धर्म संसद में अपना ऐतिहासिक भाषण 11 सितंबर 1893** को दिया था। यह आधुनिक भारतीय इतिहास की सबसे प्रसिद्ध घटनाओं में से एक है। इसने पश्चिमी दुनिया में वेदांत और योग की शुरुआत की और सार्वभौमिक भाईचारे पर जोर दिया।

❍❍❍❍